CEDSI TIMES

Your Skilling Partner...

राजस्थान सरकार ने मध्याह्न भोजन में दूध को शामिल करने के लिए 860 करोड़ रुपये की मंजूरी दी

राजस्थान सरकार ने मंगलवार को राज्य भर में कक्षा 8 तक के स्कूली छात्रों को मध्याह्न भोजन में दूध शामिल करने के लिए 864 करोड़ रुपये मंजूर किए। वर्तमान में 29 नवंबर, 2022 को शुरू की गई 'मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना' के तहत सरकारी स्कूलों में सप्ताह में दो बार मीठा-गर्म दूध परोसा जाता है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि शेष चार दिनों के दौरान कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों के लिए दैनिक मध्याह्न भोजन के पोषण मूल्य को और बढ़ावा देने के लिए अब दूध उपलब्ध कराया जाएगा।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 2023-24 के राज्य के बजट में घोषित की गई योजना को सरकारी स्कूलों, मदरसों और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में शुरू किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मध्याह्न भोजन का विकल्प चुनने वाले छात्रों को दूध भी उपलब्ध कराया जाए।

गहलोत ने मिड-डे मील में प्रतिदिन दूध शामिल करने के लिए 864 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को मंजूरी दी है.

असम अपना खुद का डेयरी ब्रांड लॉन्च करेगा

गुवाहाटी: दुग्ध किसानों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार और प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए, असम दूध के लिए एकल ब्रांड नाम लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो गुजरात के 'अमूल' और कर्नाटक की नंदिनी' के समान है। राज्य में सत्ता में उनके साथ दो साल की प्रतियोगिता की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सन्ना ने बयान दिया।।

मीडिया से बात करते हुए, सरमा ने कहा कि राज्य सरकार दैनिक सहकारी समितियों को बेचे जाने वाले दूध पर बाजार दर से 5 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त भुगतान करेगी। यह प्रक्रिया कथित तौर पर 1 जून, 2023 से शुरू होगी। इस कार्रवाई का उद्देश्य राज्य के दुग्ध किसानों को प्रोत्साहित करना और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है।

इसके अलावा, गुणवत्ता नियंत्रण बनाए रखने के लिए, राज्य में उत्पादित सभी दूध एक ही ब्रांड नाम से बेचे जाएंगे। इससे न केवल दूध की गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि असम के डेयरी उद्योग के लिए एक मजबूत ब्रांड भी स्थापित होगा ।

पिछले 10 वर्षों में तमिलनाडु में दूध उत्पादन में 45% की वृद्धि

तमिलनाडु में पिछले एक दशक में दुग्ध उत्पादन में 45% की वृद्धि हुई है, दुधारू गायों की संख्या में भी 12% की वृद्धि हुई है।

तमिलनाडु का पारिस्थितिकी तंत्र कुछ राज्यों के विपरीत जहां सहकारी संघों का एकाधिकार है, निजी खिलाड़ियों को फलने-फूलने की अनुमति देता है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुसार, राज्य में दूध उत्पादन की मात्रा 2011-12 में लगभग सात मिलियन टन से बढ़कर 2021-22 में 10 मिलियन टन से अधिक हो गई है। टी.एन. पशुपालन विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि 2019 में गायों की संख्या 45 लाख थी, जो 2012 में लगभग 40 लाख थी।

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 'दिखाता है कि तमिलनाडु देश में कुल दूध उत्पादन का सिर्फ 4.5% हिस्सा है। 2021-22 में शीर्ष 15 प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों में यह 11वें स्थान पर था।

पिछले 10 वर्षों में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की फसल हिस्सेदारी में 7.5 प्रतिशत की गिरावट, NSO रिपोर्ट

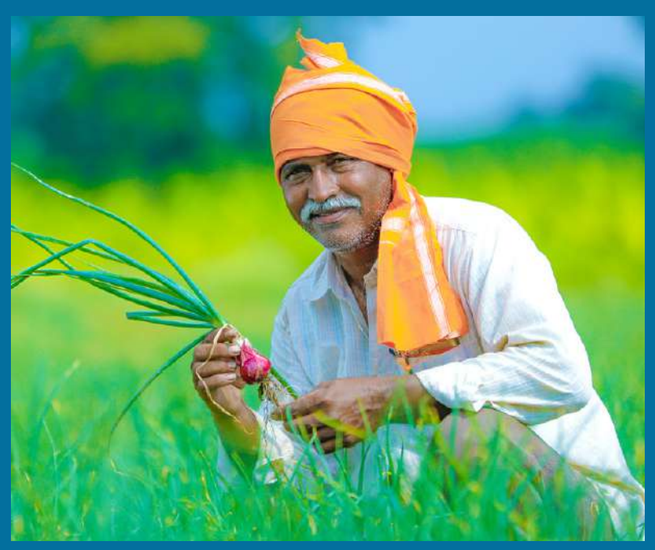

पिछले दस वर्षों में, कृषि और संबंधित उद्योगों के उत्पादन के सकल मूल्य में फसलों के अनुपात में 7.5 प्रतिशत अंक की कमी आई है। इसी अवधि के दौरान पशुधन की हिस्सेदारी में 5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है, एक रिपोर्ट द्वारा जारी की गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने इन तथ्यों को प्रदर्शित किया।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने से उत्पादन के राज्य-वार और मद-वार मूल्य पर रिपोर्ट के अनुसार, 2011-12 में फसल उप-क्षेत्र का कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 62.4% हिस्सा था, लेकिन इसका हिसाब 2020-21 में सिर्फ 54.9% होगा। कृषि और संबंधित क्षेत्रों में में पशुधन उपक्षेत्र का योगदान 2011-21 में 25.57 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 30.58 प्रतिशत हो गया है।

फसल, पशुधन, वानिकी और लॉगिंग, मछली पकड़ने और जलीय कृषि, और अन्य जुड़े हुए उद्योग चार उप-क्षेत्र हैं जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को बनाते हैं। वानिकी, लॉगिंग, मछली पकड़ने और जलीय कृषि का अनुपात भी कुछ हद तक बढ़ा है। जबकि इस दौरान मछली पकड़ने और जलीय कृषि का योगदान 4.19 प्रतिशत से बढ़कर 6.08 प्रतिशत हो गया, वानिकी और लॉगिंग का अनुपात 2011-12 से 20-21 तक 7.8 से बढ़कर 8.42 प्रतिशत हो गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने के क्षेत्रों का उत्पादन का सकल मूल्य (2011-12 के लिए स्थिर कीमतों पर), सिंचाई को छोड़कर, 2020-21 में 26.12 लाख रुपये था, जबकि 2011-12 में यह 19.08 लाख करोड़ रुपये था। 2020-21 में देश में कृषि, वानिकी और मत्स्य उद्योग के सकल मूल्य में अधिकतम योगदान देने वाले तीन राज्य राजस्थान (2.36 लाख करोड़ रुपये), महाराष्ट्र (2.46 लाख करोड़ रुपये), और उत्तर प्रदेश 3.11 लाख करोड़) था।

तेलंगाना सरकार जल्द ही अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च करेगी

शोधकर्ताओं और प्रौद्योगिकी कंपनियों ने देखा कि कृषि प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने के लिए डेटा उपलब्धता एक सीमित कारक थी। इस सीमा में बड़े पैमाने पर उपज, वर्षा, पानी की सुविधा, किसानों की जानकारी और जनसांख्यिकीय डेटा जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं। तेलंगाना सरकार विश्व आर्थिक मंच (WEF) और भारतीय विज्ञान संस्थान (IISC), बेंगलुरु के साथ एक कृषि डेटा एक्सचेंज (ADEx) प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए साझेदारी कर रही है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तकनीक का उपयोग करता है।

मंच का उद्देश्य कृषि डेटा को आसानी से सुलभ और पारदर्शी बनाना है, जो इस क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को गति प्रदान करेगा। उभरती प्रौद्योगिकियों की निदेशक रमा देवी लंका ने किसानों के लिए प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करते समय आने वाली चुनौतियों के बारे में बात की। विभिन्न कृषि सूचना प्रदाताओं (एआईपी) से डेटा को समेकित करने और इसे एक मंच पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इससे डेटा उपलब्धता की चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी। डेटा विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध है, जिसमें सरकारी विभाग, कृषि और बागवानी शैक्षणिक संस्थान और अनुसंधान केंद्र शामिल हैं।

ADEx प्लेटफॉर्म से सभी कृषि डेटा जरूरतों के लिए वन-स्टॉप शॉप प्रदान करके तेलंगाना में कृषि क्षेत्र को बदलने की उम्मीद है। प्लेटफॉर्म द्वारा एआई तकनीक का उपयोग यह सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा कि प्रदान किया गया डेटा सटीक और अप-टू-डेट है। व्यापक डेटा की उपलब्धता के साथ, कृषि क्षेत्र में किसान और अन्य हितधारक सूचित निर्णय लेने में सक्षम होंगे। इससे उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि होगी, जिससे पूरे क्षेत्र को लाभ होगा। ADEx प्लेटफॉर्म तकनीकी नवाचार के माध्यम से कृषि को बदलने के तेलंगाना सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है

दिवाली तक दूध की कीमतों में राहत नहीं: इंडियन डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष रुपिंदर सोढ़ी

इंडियन डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष रूपिंदर सिंह सोढ़ी ने कहा कि दीवाली तक दूध की कीमतें ऊंची रहेंगी, लेकिन बाद में फ्लश सीजन शुरू होने और कीमतों में गिरावट आने पर नरम हो सकती हैं।

अनाज की कीमतों में वैश्विक वृद्धि के बीच पिछले 15 महीनों में दूध की कीमतों में 13-15% की वृद्धि हुई है। बेमौसम बारिश के बाद अपर्याप्त चारे के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ, और महामारी के दौरान कम कृत्रिम गर्भाधान के कारण स्तनपान कराने वाले मवेशियों की संख्या में गिरावट आई।

व्यापार अक्टूबर से फरवरी तक फ्लश सीजन में प्रवेश करता है जब मवेशी स्वाभाविक रूप से अधिक दूध का उत्पादन करते हैं और डेयरी कंपनियां आमतौर पर अपने खरीद मूल्य को कम कर देती हैं।

अमूल डेयरी कोऑपरेटिव के पूर्व प्रबंध निदेशक सोढ़ी ने एक साक्षात्कार में कहा कि आने वाले दो वर्षों में उचित मूल्य पर दूध की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किसानों को लाभकारी मूल्य देना होगा. उन्होंने कहा कि मई तक बढ़ा हुआ ठंड का मौसम और पिछले दो महीनों में अनियमित बारिश से दूध उत्पादन में 5% की वृद्धि करने में मदद मिलेगी, गर्मियों के दौरान उत्पादन में सामान्य 15% की गिरावट के बावजूद।

सोढ़ी, जो रिलायंस रिटेल वेंचर्स के सलाहकार भी हैं, ने कहा कि अगले 25 वर्षों में भारत का दूध उत्पादन वर्तमान 222 मीट्रिक टन से बढ़कर 628 मिलियन टन हो जाएगा। कृषि के सकल घरेलू उत्पाद में पांच दशक पहले अनाज का योगदान 37% था, अब यह 17% है। दूध की हिस्सेदारी 10% से बढ़कर 24%, मांस की 1.6% से बढ़कर 8%, अंडे की 0.5% से बढ़कर 1.2% हो गई है।

जब वर्षों में समृद्धि आती है, तो उपभोक्ता खुद को कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन से प्रोटीन और पशु स्रोत से वसा युक्त आहार में अपग्रेड करते हैं। चाहे वह दूध हो या पोल्ट्री या मांस, कारण सरल है: वे स्वादिष्ट होते हैं, उच्च प्रोटीन सामग्री और सस्ती होने के कारण पौष्टिक रूप से घने होते हैं।

डेयरी उत्पादों के ब्रांड मिल्की मिस्ट में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए वेस्टब्रिज कैपिटल अंतिम चरण में है

तमिलनाडु में स्थित डेयरी उत्पाद कंपनी मिल्की मिस्ट में अल्पसंख्यक हिस्सेदारी खरीदने का सौदा भारत-केंद्रित निवेश कोष वेस्टब्रिज कैपिटल द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है, जो निजी और सार्वजनिक दोनों बाजार कंपनियों का समर्थन करता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि निवेश लगभग 800 करोड़ रुपये होने की संभावना है और मिल्की मिस्ट डेयरी फूड का मूल्य लगभग 7,000 करोड़ रुपये होगा। "बातचीत जो पिछले साल से चल रही थी अब पूरी हो चुकी है, और वेस्टब्रिज औपचारिकताओं के सभी अंतिम हिस्सों पर बंद हो रहा है।

सौदे पर इसकी विशिष्टता है, और कुछ और हफ्तों में, वित्तपोषण को आधिकारिक बना दिया जाएगा, "धन जुटाने के लिए, मिल्की मिस्ट ने पहले निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी फर्मों के साथ बातचीत की थी। हालाँकि, ये चर्चाएँ असफल रहीं। व्यवसाय ने पहले कभी संस्थानों से धन नहीं जुटाया है।

मिल्की मिस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रत्नम ने कहा, "हम धन उगाहने की संभावनाएं तलाश रहे हैं और कई कंपनियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी विशेष दावेदार को अंतिम रूप नहीं दिया है।"

उत्तराखंड में फैला गांठदार चर्म रोग; अब तक 38 गोजातीय मौत के मामले सामने आए हैं

यह रोग बुखार, बढ़े हुए सतही लिम्फ नोड्स और त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली पर कई पिंडों की विशेषता है। उत्तराखंड में पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि गोजातीय आबादी में गांठदार त्वचा रोग (एलएसडी) ने 5 मई से अब तक 38 गोजातीय जीवन का दावा किया है, जबकि बुधवार को छह लोगों की मौत हुई है। पशुपालन विभाग द्वारा जारी पशु स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार इस बीमारी से छह पशुओं की मौत हो गयी जबकि 383 पशु प्रभावित हुए।

बरामद पशुओं की संख्या 159 थी, जबकि 383 का इलाज किया गया था, बुधवार को लगभग 3,792 पशुओं का टीकाकरण किया गया था।

एलएसडी मवेशियों में होने वाला एक संक्रामक रोग है, जो पॉक्सविरिडे परिवार के एक वायरस के कारण होता है, जिसे नीथलिंग वायरस भी कहा जाता है। यह रोग बुखार, बढ़े हुए सतही लिम्फ नोड्स और त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली पर कई पिंडों की विशेषता है।

पशुपालन विभाग के मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा, “पिछले दस दिनों में 3,514 से अधिक मामलों का पता चला है, 38 मौतें हुई हैं, जबकि बुधवार शाम तक सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,648 थी और 1,828 पशुओं ने रिकवरी दिखाई, क्योंकि टीकाकरण अभियान 7,46,530 को चलाया गया था। बुधवार तक पशुओं की मृत्यु दर (सीएफआर) 1.08% थी, जबकि रिकवरी दर 52.02% थी।

रोग के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है और पशुओं के अंतर-जिला और राज्य परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के सभी अवकाश एक महीने के लिए रद्द कर दिए गए हैं, ”बहुगुणा ने कहा।

बेंगलुरु ने अपना पहला मिल्क एटीएम लगाया

मैंगलोर विश्वविद्यालय से एमबीए स्नातक विनोद गुनसेकरन को यह विचार तब आया जब उन्होंने देखा कि शहरों में लोग दिन में ताजा दूध प्राप्त करने में असमर्थ हैं और उन्होंने बेंगलुरु में पहला मिल्क एटीएम शुरू किया है। विनोद गुनासेकरन ने अपने स्टार्ट-अप वी डेयरी वेंचर्स के तहत मिल्क एटीएम (वी पाल) शुरू किया है, यह अवधारणा एटीएम में 24x7 ताजा दूध उपलब्ध कराने की है।

मशीन 24/7 अनडाइल्यूटेड और असंसाधित दूध प्रदान करती है, और मांग मजबूत रही है। मशीन 5 रुपये के सिक्के, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये के नोट स्वीकार करती है और लोग जितना दूध खरीदना चाहते हैं चुन सकते हैं। लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार दूध को कंटेनर में भर सकते हैं।

जहां दूसरी वेंडिंग मशीनें पैकेटों में दूध बेचती हैं, वहीं इस मशीन से लोग अपने बर्तनों में दूध भरते हैं; ताजा गाय का दूध हर सुबह और शाम को रिफिल किया जाता है। उन्होंने बाजार का अध्ययन करने के लिए एक वर्ष का समय लिया और मशीन में और अधिक सुविधाएँ जोड़ीं जिसके द्वारा मशीन में कार्ड सिस्टम और कार्ड को रिचार्ज करना शुरू किया गया। वर्तमान में मिल्क एटीएम होरामावु, बेंगलुरु में दो अपार्टमेंट में स्थापित है। लोग मशीन से दूध खरीदने के लिए एक विशेष डेबिट कार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं, ये 'डेबिट कार्ड' प्रीपेड कार्ड की तरह हैं, ये आरएफआईडी कार्ड मुफ्त हैं, ग्राहक कार्ड को रिचार्ज कर सकते हैं और इस एटीएम में दूध खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विनोद का कहना है कि भविष्य में बेंगलुरु और कर्नाटक के आसपास ऐसे और एटीएम लगाए जाएंगे।

हम कौन हैं?

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत भारतीय कृषि कौशल परिषद (ASCI) के तत्वावधान में काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था "भारत में डेयरी कौशल के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CEDSI)", किसानों की आजीविका के सशक्तिकरण और बेहतरी में मदद करने के लिए, वेतनभोगी कर्मचारी, और डेयरी मूल्य श्रृंखला में अन्य हितधारक।

सीईडीएसआई सदस्यता उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं, विकास चिकित्सकों, डेयरी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, छात्रों और किसानों को डेयरी उद्योग के लिए आसन्न महत्व के मुद्दों पर बहस और चर्चा करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगी।

CEDSI

Centre of Excellence for Dairy Skills in India

Join Our Membership Drive and Get Benefits of

- Platform to interact with other members in the sector
- Networking opportunities with corporate leaders and government authorities
- Special costs of training in Skill India Certified Programmes
- Access to our Journal and Publications
- Expert advice in day-to-day operations and management of livestock /farm productions
- Free registration on the job portal and regular updates on job vacancies in the sector
- Recognize your organization with CEDSI Yearly Awards and Recognition
- Chance to reach across the board through advertising in our press releases, news and articles
- Consultative and advisory services to help members
- Consulting and advisory services to help members
- Periodic e-newsletter for the latest news, govt. announcement and schemes in dairy sectors
- Updates on training programs of CEDSI and access to the training calendar

Who Can Become a Member -

Corporates/ Cooperatives

NGO's/CSR Foundations

Dairy Farmers

Students

Professional

www.cedsi.in

@cedsi_india